RAJYA SABHA

Monday, the 30th July, 1984/8 Sravana, 1906 (Saka)

The House met at eleven of the clock; Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Pollution Control System in Power Plants

*101. SHRI RAM NARESH KUSHAWAHA:†

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that according to the Central Pollution Control Board most of the thermal power plants in the country have shown indifferent attitude towards air pollution caused by the plants and that in most of the cases the pollution control system in the power plants is not functioning properly; and

(b) if so, what are the details in this regard and what action has been taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) There has been a press report to this effect, citing a statement by the Chairman of the Central Pollution Control Board.

(b) Thermal power stations of older designs have poorer pollution control devices since at the time of their construction, electrostatic precipitators (ESPs) of requisite efficiency were not being manufactured. Further, quality of coal has affected the performance of ESPs in some cases. These units—18 in all—are being included for retrofitting of improved ESPs under the renovation and modernisation scheme. In so far as the NTPC installations and new thermal plants of 200 MW and above are concerned, electro-static precipitators are functioning efficiently.

श्री राम नरेश कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष महोदय, सभापति जी यह देश में कुल 48 थर्मल पावर यूनिट होंगे जिनमें से 6 सही सलामत काम कर रहे हैं और 17 को आप मरम्मत का काम कराने जा रहे हैं कि पोल्यूशन नहीं करेगा यानी 23 हुए, बाकी 25 धुआं उगलते रहेंगे और प्रदूषण करते रहेंगे, तो कब तक यह प्रदूषण चलता रहेगा, उन 25 का क्या होगा और सब से ज्यादा पोल्यूशन वह तो हमारे यहां का भद्रपुर कर रहा है। भद्रपुर मे 2 हजार से लेकर 5 हजार मिलिग्राम पर मीट्रिक क्यूबिक पर ईयर वह पोल्यूशन करता है तो इसका क्या उपाय आप कर रहे है जो यहां पर इतना धुआं उगल करके प्रदूषण कर रहा है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : चेयरमैन साहब मैंने पहले ही निवेदन किया 18 पावर स्टेशन हमारे ऐसे हैं जिनको माडर्नाइजेशन और रेनोवेशन की जो स्कीम है 5 सौ करोड़ रुपए की उसके अंतर्गत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिनको उस सूची में शामिल किया गया है। यह कहना सही नही है कि केवल 6 स्टेशन ठीक से काम कर रहे हैं।

श्री सभापति : नजदीक से नजदीक स्टेशन की क्या हालत है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : भद्रपुर नया स्टेशन नहीं है, भद्रपुर पुराना स्टेशन है, लेकिन भद्रपुर में भी इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपीटेटर लगाए गए हैं और एक चिमनी जिसके बारे में शिकायत है उसके बारे में भी चेयरमैन साहब एक समस्या यह है कि जब नया इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपीटेटर उसके अन्दर लगाया तो कम से कम 6 महीने तक उस पावर प्लांट को बंद रखना पड़ेगा। बिजली की कमी के कारण स्थिति हमें इस बात की इजाजत नही देती कि हम बिजली उत्पादन करने

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ram Naresh Kushawaha.

वाले यूनिट्स को 6 महीने तक बद रखें इसलिए उसको प्लानिंग करके पहले से योजना बना करके जो बंद रखने का समय होता है, अवधि होती है, उसके अन्दर ही इन सारी पुरानी यूनिट्स को जिनके अन्दर इलैक्ट्रास्टेटिक प्रैसीपिटेटर नहीं हैं या इस प्रकार के यन्त्र नही हैं वहां पर यह यंत्र का लगाने का योजनाबद्ध काम किया जा रहा है ।

श्री राम नरेश कुशवाहा : मान्यवर, यह वाटर पोल्यूशन का मिनिमम एवरेज 150 मिलीग्राम है और यह 5-5 हजार हो रहा है । इसका फलाई एश या इसका क्या कोई दूसरा उपयोग भी हो सकता है ?

जिससे कुछ जैसी मेरी जानकारी में इसी अखबार में है, उससे कोई नीति बनाई जा सकती है और वर्तमान के मुकाबले काम में आएगी । अगर ऐसा है, तो इस पर सरकार क्या विचार कर रही है, क्या सोच रही है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन्, रिसर्च एंड डवलपमेंट का काम हो रहा है और माननीय सदस्य ने जो बात बताई है, जो सुझाव दिया है, उसकी तरफ भी हम जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, उनका ध्यान दिलाएंगे और कोशिश यही है कि इसका भी इस्तेमाल किया जा सके ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित श्रीमान् मेरा प्रश्न है । मंत्री जी का यह उत्तर है कि जो कोयले की क्वालिटी है उसके कारण भी मशीन के निष्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है । तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कोयले का उत्पादन कहां पर होता है और कोयले की सप्लाई किस विभाग से होती है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन् कोयला विभाग से हो होती है, जो इसी मंत्रालय का एक विभाग है ।

श्री सत्यप्रकाश मालवीय : उसका उत्पादन प्रोडक्शन कहां होता है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन, कोयला खानों में ।

श्री सभापति : यह तो अनाड़ी भी जानता है, मगर कौन कौन सी जगह हैं . . .

श्री आरिफ मोहम्मद खान : श्रीमन, मैं इसलिए जवाब दे रहा था । मंत्रालय तो एक ही है । विद्युत विभाग और कोयला विभाग अलग हैं और माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कोयले के संबंध में क्या किया जा रहा है । तो कोयले के संबंध में कोयला विभाग इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वाशरीज लगाएंगे, क्रशर लगाएंगे और ज्वायंट सैंपलिंग के लिए भी तैयार हो गया है । कोशिश यह है कि कोयले के कारण जहां कहीं प्रदूषण बढ़ता है, उसमें भी कोयले की क्वालिटी को बेहतर बनाकर नियंत्रित किया जाए । उसमें कोल-हैंडलिंग प्लांट भी लगाए जा रहे हैं । उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए यह काम किए जा रहे है । मैं माफी चाहता हूं कि वह जवाब दिया, कोयला विभाग मैं देखता नहीं हूं ।

श्री सभापति : मैं तो इसलिए परेशान हूं कि रोज ही फरनीचर पर लोग अपना नाम लिख देते हैं ।

श्री अश्विनी कुमार : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत जो राख निकल रही है, उसके बारे में कहा कि स्टेबलाइजर लगाए जाएंगे ठीक किया जाएगा । उन्होंने कहा कि जब तक पावर प्लांट छः महीने बंद नहीं होगा, वे लगाए नही जा सकते । देश में बिजली की हालत इतनी ख[illegible] है कि एक भी प्लांट जो चल सकता है, उसको बंद करने की क्षमता है । उसका

स्वाभाविक कारण होता है और इस प्रकार से बंद करना कठिन होगा और जो मैं अनुभव कर रहा हूं अपने राज्य के अंदर जो बारौनी में थर्मल पावर है, उसकी भी जो हालत है, अगर आप वहां जाकर मंत्री महोदय देखेंगे तो गंगा से एक किलोमीटर है, वह एक किलोमीटर का जो सारा क्षेत्र है, उसमें करीब चार फीट, पांच फीट राख की परत जम गई है और जमकर गंगा में हर साल लाखों टन जा रही है और पूर्व में जो गंगा बहती है, उसमें पानी पीने के लिए जा रहा है, उसमें बराबर राख आती है। जब हवा चलती है, तो बारौनी थर्मल पावर के जो मकानात हैं, रिफाइनरी के मकानात हैं, जैसा आपने निवेदन किया सभापति महोदय, लोग फर्नीचर पर कोयले की राख की तरह नाम लिख देते हैं, वहां पर गृहणियों को सिवा राख साफ करने के कोई काम नहीं है और मजदूरों को वह राख साफ करने से कितनी तपेदिक की बीमारियां हो रही हैं, यह प्रश्नवाचक चिह्न बन गया है। यह मैंने आपको एक बरौनी का बताया। मैं यह पूछना चाहूंगा कि बरौनी में जो इस प्रकार की स्थिति है रिफाइनरी, फर्टीलाइजर, थर्मल पावर तीनों की राख आ रही है और गंगा में भी भयानक प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए बिजली विभाग और कोयला विभाग, दोनों चूंकि आज हमारे एक ही मंत्री के पास हैं, उसके सुधार के लिए कुछ करेंगे, क्या आप इस बारे में आश्वासन दे सकेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खान : यह जो माननीय सदस्य ने समस्या बताई हमारा ध्यान दिलाया, निश्चित ही उसको देखेंगे, उसमें जो कुछ भी संभव हो सकता है, उसको ठीक करने के लिए कदम उठाएंगे। हालांकि यह जो पावर स्टेशन है, यह प्रदेश सरकार का है और राज्य विद्युत परिषद के अंतर्गत आता है। इसलिए उनका भी इस ओर ध्यान आए, वह ध्यान दिलाएंगे।

MR. CHAIRMAN: We will take up Question No. 102 and 114 together because they are identical.

SHRI SHRI SHANKAR: Sir, they are not identical. The first deals with Haldia Petrochemical Complex and the second pertains to the petrochemical complexes in general.

MR. CHAIRMAN: I thought that by combining them we will dispose them of together.

Setting up of Haldia Petro-Chemical Complex

*102. SHRI SUKOMAL SEN:†
SHRI INDRADEEP SINHA:

Will the Minister of ENERGY be pleased to refer to the answer to Unstarred Question No. 903 given in the Rajya Sabha on the 7th May, 1984 and state:

(a) what is the present position of the proposal for setting up of Haldia Petrochemical Complex; and

(b) whether any other petrochemical complex is proposed to be set up in any other State in the near future; and if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PETROLEUM IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI GARGI SHANKAR MISHRA): (a) The revised feasibility report is under study. The State Government has been informed that it will not be possible for the Central Government to participate in the project as a joint venture partner, and that the State Government may take action to implement the project. The Central Government will give technical and other assistance which the State Government may require in implementing the project. A similar decision has also been taken with regard to the request of the Gujarat Government for a petro-chemical complex in that State.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sukomal Sen.